Arising out of Order-in-Original: IV/16-16/MISC/RGN/16-17Date: 08.08.2016 Issued by: Assistant Commissioner, Central Excise, Din: Mehsana, A'bad-III.

ध अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. Priyakantju Pack

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

## भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

## Revision application to Government of India:

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूवोक्त धारा को उप—धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।
- (i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:
- (ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।
- (ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.
- (ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।
- (b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (C) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

- ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।
- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए—8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल—आदेश एवं अपील आदेश की दो—दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35—इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर—6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/— फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/— की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:--Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35— णबी / 35—इ के अंतर्गत:— Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं
- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.
- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ—20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद—380016.
- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.
- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपन्न इ.ए—3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/— फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/-where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any

gystar of a branch of a

nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार . उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.६.५० पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall beer a court fee stamp of Rs.6.50 paisa as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९४४ की धारा ३५फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-२) अधिनियम २०१४(२०१४ की संख्या २५) दिनांक: ०६.०८.२०१४ जो की वित्तीय अधिनियम, १९९४ की धारा ८३ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
- सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

- (6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती हैं।
- (6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

## ORDER-IN-APPEAL

This appeal has been filed by M/s Priyakantju Pack, S No.117-P1 P1, Vill-Karoda, Chansma, Patan, Gujarat [hereinafter referred to as "the appellant"] against Order-in-Original F No.IV/16-16/Misc/rgn/16-17-II dated 08.08.2016 [impugned letter] passed by the Assistant Commissioner of Central Excise, Division-Mehsana [the Assistant Commissioner].

- Briefly stated, the facts of the case is that the appellant had applied for registration 2. of their manufacturing unit, vide their application 22.04.2014 before the jurisdictional Central Excise office which was acknowledged as registration No.AMTPP5822AEM001. Since the said registration was not operative through ACES login, as system was blocked by the Central Excise Officer, they have filed another application with same PAN number and address on 04.05.2016. The said application was also acknowledged as registration No. AMTPP5822AEM002. However, the fact remain that they were not allowed to operation their earlier registration number and unable to file periodical returns. In the circumstances, the appellant has requested vide their letter dated 22.06.2016 to the jurisdictional central excise office to allow them to operate their registration No.AMTPP5822AEM001 and cancel the registration No.AMTPP5822AEM002. Vide impugned letter dated 08.08.2016, the Assistant Commissioner has not accepted the request of the appellant as their request found to be an afterthought action after a period of two years. By denying the request, the Assistant Commissioner has also informed that their registration was revoked by the competent authority at the material time.
- 3. Being aggrieved with the impugned letter dated 08.08.2016, the appellant has filed the present appeal on the grounds that:
  - Neither Rule 9 of Central Excise Rules nor any provisions of the Central Excise
    Law makes a manufacturer of trader of excisable goods not to obtain registration
    from where he may be undertaking manufacturing or trading; that Rule 9 of the
    Central Excise Rules mandates every manufacturer to obtain registration for their
    premises where excisable goods are manufactured.
  - The Assistant Commission could not have been rejected application when there were weighty and relevant reasons also on the appellant's part for obtaining a registration for manufacture of goods and the therefore the rejection order passed is unreasonable and arbitrary manner.
  - The scheme of registration under notification No.35/2001-CE (NT) are applicable
    with full vigour in their case and the order of rejection is contrary to the said
    notification; that no prejudice would be caused to the department if a registration
    was issued in favour of them, allowing to file statutory returns for the relevant
    period for the goods manufactured.
  - Department may reject any registration following the mandate given in the notification No.35/2001-CE, however, in the present case no such condition for cancellation of registration exists; that the appellant shall be given a reason opportunity to represent their case against the proposed cancellation as provided in para 12 of the said notification.



- 4. A personal hearing in the matter was held on 15.03.2017. Shri P.P.Jadeja, Authorized Representative and Shri Bharat Patel, Authorized signatory appeared for the same and reiterated the grounds of appeal. They further submitted that as per their request letter dated 22.06.2016, the appellant should be allowed the first registration; that the first registration was blocked/cancelled without following the due procedure.
- 5. I have carefully gone through the facts of the case and submissions made by the appellant. The limited point to be decided in the instant case is relating to denial of central excise registration.
- 6. At the outset, I observe that the Assistant Commissioner has denied the request dated 22.06.2016 of the appellant vide his letter dated 08.08.2016 stating that their said request has been made after a period two years of their first application dated 22.04.2014 for central excise registration which found to be an afterthought action. He further informed that their registration was revoked by the competent authority at the material time.
- 7. Rule 9 of the Central Excise Rules, 2002 provides that "every person who produces, manufacturers, carries on trade, holds private storeroom or warehouse or otherwise uses excisable goods shall get registered. Sub-rule (3) of the said rule provides that the registration shall be subject to such conditions, safeguards and procedures, as may be specified by notification by the Board. Notification No.35/2001-CE (NT) dated 26.06.2001 stipulates certain conditions, safeguards and procedures for registration. As per conditions and safeguards stipulates in the said notification "A registration certificate granted under this rule may be revoked or suspended by the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, if the holder of such certificate or any person in his employment, is found to have committed breach of any of the provisions of the Act or the rules made there under or has been convicted of an offence under Section 161, read with Section 109 or with Section 116 of the Indian Penal Code (45 of 1860)."
  - 8. Registration to manufacture excisable goods is a substantive right under residuary provisions of Rule 9 read with notification *supra* and such registration can be revoked or suspended only if the holder of the registration certificate or any person in his employment is found to have committed breach of provisions of the Central Excise Act or Rules or convicted of an offence under India Penal Code. In the instant case, I observe that in the impugned letter dated 08.08.2016, the Assistant Commissioner has failed to noted the reasons for invoking or suspending the registration in question and as can be seen from the said impugned letter, the Assistant Commissioner has not given any finding as to the emergence of invocation or cancellation of the registration.
  - 9. In view of above discussion, I order that the appellant may be allowed to operate their central excise registration, if they fulfill the conditions, safeguards and procedures as prescribed under notification No.35/2001-CE. If not found proper, facts like a



deliberate, intentional and clear involvement of appellant in any offences defrauding the Revenue by doubtful means, should be taken into account and pass a speaking order to that effect.

10. In view of above discussion, I remand the case to the Assistant Commissioner for considering the case afresh in above terms.

ुकाश्चेग्भ (उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स - I) Date:१७/03/2017

<u>Attested</u>

(Mohanan V.V)
Superintendent (Appeals-I)
Central Excise, Ahmedabad
By R.P.A.D.

To M/s Priyakantju Pack, S No.117-P1 P1, Vill-Karoda, Chansma, Patan, Gujarat

## Copy to:-

- The Chief Commissioner, Central Excise Zone, Ahmedabad.
- 2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-III
- 3. The Addl./Joint Commissioner, (Systems), Central Excise, Ahmedabad-III
- 4. The Dy. / Asstt. Commissioner, ST Division-Mehsana, Ahmedabad-III Guard file.
- 6. P.A file.

